

विधि (Law)

RAS Mains Paper 3 | Unit 3 | Part B



**NEW INDIA
EDUCATION (NIEd)**

— संकल्प आपका, साथ हमारा —

RAS MAINS EXAM

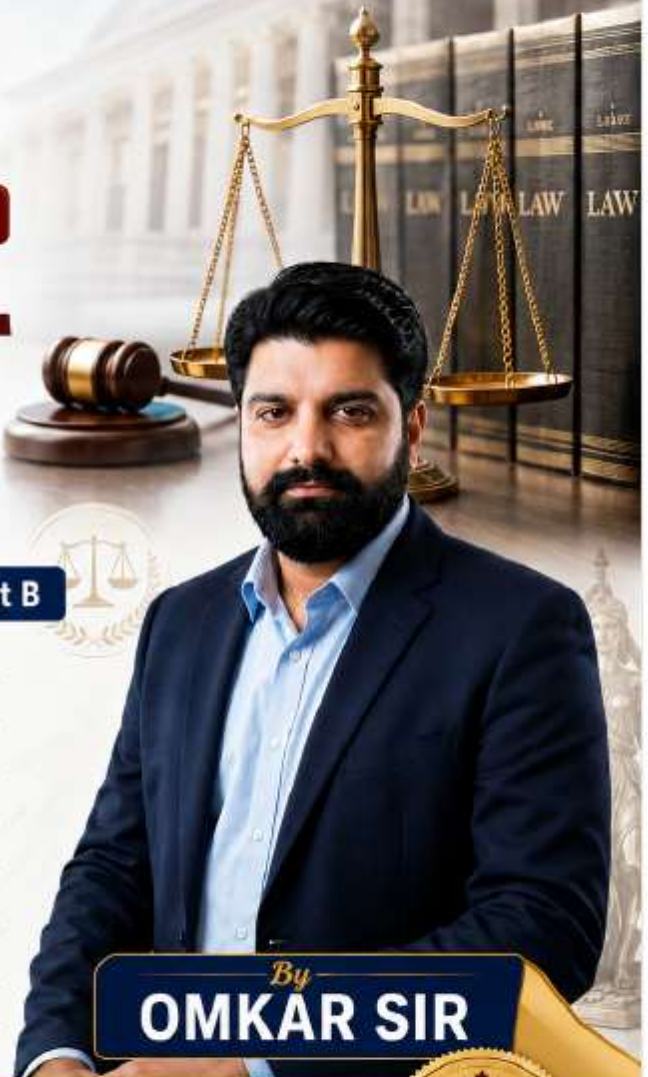
विधि (Law)

RAS Mains – Paper 3

Unit 3

Part B

-  सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI)
-  सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act)
-  बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
-  महिला एवं बाल कानून — भाग 1
-  POCSO अधिनियम
-  वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम
-  राजस्थान काशतकारी अधिनियम
-  राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
-  BNS + BNSS



By
OMKAR SIR



सरल भाषा में
सम्पूर्ण कवरेज



परीक्षा की दृष्टि से
महत्वपूर्ण बिंदु



चार्ट, डायग्राम और
मैप्स सहित



नवीनतम संशोधन
एवं अपडेट सहित



RAS Mains के लिए
विशेष रूप से उपयोगी

RAS

अभ्यर्थियों के लिए
सर्वश्रेष्ठ अध्ययन
सामग्री

📋 विषय-सूची (Index) — इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे?

1. विधि (Law) क्यों पढ़ें? — RAS अधिकारी और कानूनी दायित्व
2. RAS Mains 2026 — नया Pattern (केवल 5-अंक और 10-अंक प्रश्न)
3. Unit 3 Part B का पूर्ण पाठ्यक्रम (Complete Syllabus Overview)
4. अध्याय 01: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act)
5. अध्याय 02: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act)
6. अध्याय 03: बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights — IPR)
7. अध्याय 04: घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA)
8. अध्याय 05: POSH अधिनियम, 2013 + POCSO अधिनियम, 2012
9. अध्याय 06: माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007
10. अध्याय 07: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (Rajasthan Tenancy Act)
11. अध्याय 08: राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 (Rajasthan Land Revenue Act)
12. अध्याय 09: भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) + भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)
13. परीक्षा महत्व — मुख्य तथ्य (Key Facts) + PYQs + ऐतिहासिक क्रम (Timeline)

कल्पना कीजिए — आप एक RAS अधिकारी (IAS/RAS Officer) हैं। सुबह 9 बजे एक किसान आता है — पटवारी ने खसरा-खतौनी देने से मना किया। दोपहर में एक महिला घरेलू हिंसा (Domestic Violence) की शिकायत लेकर आती है। शाम को OTP fraud का शिकार एक युवक आता है। रात को एक 75 वर्षीय बुजुर्ग पिता बताते हैं कि बेटे ने घर से निकाल दिया। यह एक काल्पनिक दिन नहीं — यह हर RAS अधिकारी की वास्तविक दिनचर्या है। इन सभी परिस्थितियों में आपका सबसे बड़ा हथियार है — विधि (Law) का ज्ञान!

1. विधि (Law) क्यों पढ़ें? — RAS अधिकारी और कानूनी ज्ञान

RAS (Rajasthan Administrative Service) अधिकारी केवल प्रशासक (Administrator) नहीं होता — वह कानून का रक्षक (Custodian of Law) भी होता है। जन-सामान्य को न्याय दिलाना, कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना और संविधान की भावना के अनुरूप कार्य करना — यह सब विधि (Law) के गहरे ज्ञान के बिना संभव नहीं है।

💡 एक RAS अधिकारी का दिन — विधि से जुड़े 5 मामले

सुबह 9 बजे: रामलाल (किसान) — पटवारी ने खसरा-खतौनी देने से मना किया। → सूचना का अधिकार (RTI) Act 2005 के तहत आवेदन दाखिल होगा। | दोपहर 12 बजे: सीता बाई — पति ने मारपीट की और घर से निकाला। → PWDVA 2005 के तहत संरक्षण आदेश (Protection Order) मिलेगा। | दोपहर 3 बजे: व्यापारी की brand copy की जा रही है। → IPR कानून के तहत ट्रेडमार्क (Trademark) उल्लंघन की कार्रवाई। | शाम 6 बजे: OTP fraud — बैंक खाते से 50,000 रु. गए। → IT Act 2000, धारा (Section) 66C के तहत FIR। | रात 8 बजे: 78 वर्षीय बुजुर्ग माँ को बेटे ने घर से निकाला। → Senior Citizens Act 2007 के तहत Tribunal में आवेदन।

1. न्यायिक चेतना (Legal Awareness): नागरिकों के अधिकारों (Rights) और कर्तव्यों (Duties) की सटीक जानकारी।
2. जन-शिकायत निवारण (Grievance Redressal): RTI, PWDVA, POSH जैसे अधिनियमों के तहत शिकायतों का त्वरित निपटान।
3. भूमि प्रशासन (Land Administration): राजस्थान में काश्तकारी (Tenancy) और भूमि राजस्व (Land Revenue) कानून अत्यंत महत्वपूर्ण।
4. नागरिक सुरक्षा (Citizen Protection): BNS और BNSS 2023 के तहत नई आपराधिक प्रक्रिया का ज्ञान अनिवार्य।
5. डिजिटल युग (Digital Era): साइबर अपराध (Cyber Crime) और IT Act 2000 का ज्ञान अपरिहार्य।

महत्वपूर्ण (Important): RAS Mains Paper 3, Unit 3, Part B में विधि (Law) से 9 अध्याय हैं। यह Unit सबसे विस्तृत है और प्रश्नों में सर्वाधिक विविधता है। 2026 के नए RPSC Pattern में केवल 5-अंक और 10-अंक के प्रश्न आएंगे।

2. RAS Mains 2026 — नया परीक्षा Pattern [New Examination Pattern]

RPSC (Rajasthan Public Service Commission) ने वर्ष 2026 से RAS Mains परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। 2-अंक के प्रश्न पूरी तरह समाप्त — अब केवल 5-अंक और 10-अंक के प्रश्न। इसका अर्थ है — रटने (Mugging) से नहीं, समझने (Understanding) और लिखने (Writing) से सफलता मिलेगी।

पुराना Pattern (Old Pattern)	नया Pattern 2026 (New Pattern)
◆ 2-अंक के प्रश्न (Short Questions) भी होते थे ◆ 30-40 शब्दों में उत्तर पर्याप्त था ◆ Factual और Recall-based questions अधिक ◆ रटने (Mugging) पर निर्भरता ज्यादा ◆ Conceptual depth कम आवश्यक थी ◆ Short definitions से काम चलता था	◆ 2-अंक प्रश्न पूरी तरह समाप्त ❌ ◆ केवल 5-अंक और 10-अंक प्रश्न ✅ ◆ 70-80 और 130-150 शब्दों में उत्तर ◆ Conceptual clarity और Analysis जरूरी ◆ उत्तर-लेखन कौशल (Writing Skill) महत्वपूर्ण ◆ Current Affairs link से उत्तर distinct बनेगा

5-अंक प्रश्न (5-Mark Questions) — लघु उत्तरीय (Short Answer Type)

1. शब्द सीमा (Word Limit): लगभग 70-80 शब्द
2. संरचना (Structure): परिभाषा (Definition) + 2-3 मुख्य प्रावधान + 1 उदाहरण + 1 line निष्कर्ष
3. Pattern: "धारा XX क्या है? उसके प्रावधान बताइए।"
4. उदाहरण: "सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अपवाद क्या हैं?" (5 अंक)

10-अंक प्रश्न (10-Mark Questions) — दीर्घ उत्तरीय (Long Answer Type)

1. शब्द सीमा (Word Limit): लगभग 130-150 शब्द
2. संरचना (Structure): परिचय → मुख्य प्रावधान → विश्लेषण → RAS भूमिका → निष्कर्ष
3. Pattern: "...विस्तार से वर्णन करते हुए प्रशासनिक प्रासंगिकता बताइए।"
4. उदाहरण: "RTI अधिनियम की धाराओं का विस्तृत वर्णन करते हुए RAS अधिकारी की भूमिका बताइए।" (10 अंक)

💡 उत्तर-लेखन रणनीति (Answer Writing Strategy) — 2026 नया Pattern

5-अंक उत्तर: [1] परिभाषा या परिचय (15-20 शब्द) → [2] 2-3 मुख्य प्रावधान (30-40 शब्द) → [3] 1 concrete उदाहरण (15-20 शब्द) → [4] निष्कर्ष 1 line। | 10-अंक उत्तर: [1] Act का background/purpose (20-25 शब्द) → [2] मुख्य धाराएं numbered format (70-80 शब्द) → [3] विश्लेषण / RAS भूमिका (25-30 शब्द) → [4] निष्कर्ष (10-15 शब्द)। | याद रखें: RPSC Clarity, Accuracy और Relevance देखती है — लंबे उत्तर नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है।

3. Unit 3 Part B — पूर्ण पाठ्यक्रम विवरण [Complete Syllabus Overview]

RAS Mains Paper 3, Unit 3, Part B में कुल 9 अध्याय हैं — 6 केंद्रीय अधिनियम (Central Acts), 2 राजस्थान राज्य अधिनियम (Rajasthan State Acts) और 2 नई आपराधिक संहिताएं (BNS व BNSS 2023)। नीचे सभी 9 अध्यायों का संक्षिप्त विवरण और परीक्षा महत्व:

अध्याय	अधिनियम (Act)	मुख्य धाराएं	प्रकार
01	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act)	धाराएं 1-20 (सभी)	केंद्रीय
02	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act)	Sec 1, 2, 65, 66, 66B-F, 67, 67A-C, 71-78	केंद्रीय
03	बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)	Patent, Copyright, Trademark, GI, TRIPS	अवधारणा
04	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA)	धाराएं 1-29, 31	केंद्रीय
05	POSH Act 2013 + POCSO Act 2012	POSH: 1-9, 11-20 POCSO: 1-15	केंद्रीय
06	माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007	धाराएं 1-25	केंद्रीय
07	राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955	Sec 1, 5, 14-17A, 31-37, 38-54A, 206-242	राज्य
08	राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956	Sec 1-3, 4-36, 40A, 74-87, 106-183	राज्य
09	BNS 2023 + BNSS 2023	BNS: 1,2,189-197,270,294-296 BNSS: 1,2,14-17,41-43 आदि	केंद्रीय

4. अध्याय-वार सॉक्षिप्त परिचय [Chapter-wise Brief Introduction]

अध्याय 01 — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 [RTI Act, 2005]

यह अधिनियम नागरिकों को किसी भी सरकारी दफ्तर से जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार (Legal Right) देता है। RAS अधिकारी इस अधिनियम में लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer — PIO) की भूमिका निभाता है।

- ◆ धाराएं 1-20 — सभी sections पाठ्यक्रम में
- ◆ लोक प्राधिकरण (Public Authority) — धारा 2(h)
- ◆ सूचना देने की समय-सीमा — धारा 7: 30 दिन; जीवन-मृत्यु मामलों में 48 घंटे
- ◆ अपवाद (Exemptions) — धारा 8: 10 श्रेणियां
- ◆ प्रथम अपील (First Appeal) — धारा 19(1) | द्वितीय अपील — धारा 19(3) सूचना आयोग
- ◆ दंड (Penalty) — धारा 20: 250 रु./दिन, अधिकतम 25,000 रु.

अध्याय 02 — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 [IT Act, 2000]

डिजिटल युग में साइबर अपराध (Cyber Crime) से निपटने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (Electronic Signature) और साइबर दंड (Cyber Penalty) के विस्तृत प्रावधान हैं।

- ◆ धारा 2 — 14 महत्वपूर्ण परिभाषाएं (Definitions) — पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट
- ◆ धारा 65 — कंप्यूटर स्रोत कोड से छेड़छाड़ (Source Code Tampering): 3 वर्ष कारावास
- ◆ धारा 66C — पहचान चुराना (Identity Theft): 3 वर्ष + 1 लाख रु. जुर्माना
- ◆ धारा 66A — 2015 में Supreme Court ने असंवैधानिक घोषित किया (Shreya Singhal Case)
- ◆ धारा 67 — अश्लील सामग्री प्रकाशन (Obscene Material Online): 3-5 वर्ष

अध्याय 03 — बौद्धिक संपदा अधिकार [Intellectual Property Rights — IPR]

बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) किसी व्यक्ति की मानसिक रचना है — आविष्कार, साहित्यिक कृति, कला, व्यापारिक नाम आदि। इनकी सुरक्षा के लिए अलग-अलग कानून हैं।

- ◆ पेटेंट (Patent) — नए आविष्कारों की 20 वर्षीय सुरक्षा
- ◆ कॉपीराइट (Copyright) — साहित्यिक व कलात्मक कृतियां: मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक
- ◆ ट्रेडमार्क (Trademark) — व्यापारिक चिह्न: 10 वर्ष, नवीकरणीय
- ◆ भौगोलिक संकेत (Geographical Indication — GI) — जैसे Rajasthan का जोधपुर मिर्ची, बगरू प्रिंट

- ◆ TRIPS Agreement — 1995 में WTO के तहत भारत सदस्य

अध्याय 04 — घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 [PWDVA, 2005]

यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू संबंधों में होने वाली हिंसा से व्यापक सुरक्षा देता है। घरेलू हिंसा में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा — सभी शामिल हैं।

- ◆ धाराएं 1-29 और 31 — सभी पाठ्यक्रम में
- ◆ घरेलू हिंसा (Domestic Violence) की परिभाषा — धारा 3: 4 प्रकार
- ◆ संरक्षण आदेश (Protection Order) — धारा 18
- ◆ निवास आदेश (Residence Order) — धारा 19: घर में रहने का अधिकार
- ◆ संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) — धारा 9: महिला अधिकारी को प्राथमिकता

अध्याय 05 — POSH Act 2013 + POCSO Act 2012

POSH Act महिलाओं को कार्यस्थल (Workplace) पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देता है। POCSO Act 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित करता है।

- ◆ POSH: आंतरिक शिकायत समिति (ICC) — धारा 4: 10+ कर्मचारियों पर अनिवार्य
- ◆ POSH: यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) की परिभाषा — धारा 2(n)
- ◆ POCSO: अनिवार्य रिपोर्टिंग (Mandatory Reporting) — धारा 19: न रिपोर्ट करना भी अपराध
- ◆ POCSO: विशेष न्यायालय (Special Court) में camera trial — बच्चे की पहचान गोपनीय

अध्याय 06 — माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007

यह अधिनियम माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens — 60 वर्ष से अधिक) के भरण-पोषण (Maintenance) और कल्याण (Welfare) की कानूनी गारंटी देता है।

- ◆ धाराएं 1-25 — सभी पाठ्यक्रम में
- ◆ न्यायाधिकरण (Tribunal) — SDM की अध्यक्षता — 90 दिन में निर्णय
- ◆ भरण-पोषण राशि — धारा 9: अधिकतम 10,000 रु./माह (Rajasthan)
- ◆ वृद्धाश्रम (Old Age Home) — धारा 19: प्रत्येक जिले में

अध्याय 07 — राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 [Rajasthan Tenancy Act, 1955]

यह राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण भूमि सुधार (Land Reform) कानून है। काश्तकारों (Tenants/Kasthkars) के अधिकारों की रक्षा और भूमि उपयोग, लगान (Rent), बेदखली (Ejectment) के नियम तय करता है।

◆ धारा 5 — 31 परिभाषाएं (Definitions) — सभी पाठ्यक्रम में

- ◆ काश्तकार (Tenant) के प्रकार — धाराएं 14-17A: खातेदार, गैर-खातेदार आदि
- ◆ लगान (Rent) — धाराएं 31-37 | बेदखली (Ejectment) — धाराएं 38-54A
- ◆ राजस्व न्यायालय (Revenue Courts) — धाराएं 206-232 | अपील — 239-242

अध्याय 08 — राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 [Rajasthan Land Revenue Act, 1956]

यह अधिनियम राजस्थान के राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) का मूल आधार है। भूमि की पैमाइश (Survey), राजस्व वसूली (Revenue Collection) और राजस्व अधिकारियों की शक्तियों का विस्तृत वर्णन।

◆ धाराएं 1, 2, 3 — शीर्षक, क्षेत्र और परिभाषाएं

- ◆ राजस्व अधिकारी (Revenue Officers) — धाराएं 4-36: पटवारी → तहसीलदार → SDM → Collector
- ◆ भूमि उपयोग (Land Use) — धाराएं 74-87 | वर्गीकरण — 106-137
- ◆ राजस्व वसूली (Revenue Recovery) — धाराएं 142-183

अध्याय 09 — भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) + भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS)

1 जुलाई 2024 से भारत में नई आपराधिक संहिताएं लागू हुईं। IPC 1860 की जगह BNS 2023 और CrPC 1973 की जगह BNSS 2023 आई। RAS अधिकारी के लिए यह सबसे current topic है।

◆ BNS 2023 — IPC 1860 का स्थान; BNSS 2023 — CrPC 1973 का स्थान (1 जुलाई 2024 से)

- ◆ BNS पाठ्यक्रम: धारा 1, 2, 189-191, 194-197, 270, 294-296
- ◆ BNSS पाठ्यक्रम: धारा 1, 2, 3(2)(a)(b), 14-17, 41-43, 126-129, 148-149, 152, 163-167, 173, 174, 187, 194-196
- ◆ बड़े बदलाव: Zero FIR, 45 दिन में trial, 7 वर्ष से अधिक अपराधों में forensic अनिवार्य

5.. इस विषय को कैसे पढ़ें? [Smart Study Strategy]

1. Story First: हर Act की शुरुआत एक real-life situation से करें। Context समझने पर provisions अपने आप याद होते हैं।
2. Definitions 3-Step Format में: कानूनी परिभाषा → सरल भाषा → दैनिक जीवन उदाहरण।

3. Section Numbers याद करें: RAS exam में exact section numbers लिखने से marks बढ़ते हैं।
4. 5-mark vs 10-mark अलग-अलग practice: दोनों के लिए अलग template बनाएं।
5. PYQs (2013-2024) पहले solve करें: Pattern समझने का सबसे अच्छा तरीका।
6. Current Affairs link करें: BNS/BNSS changes, NCRB data — उत्तर को distinct बनाते हैं।
7. Rajasthan Context जोड़ें: जहाँ भी possible हो, Rajasthan के examples दें।

🎯 विधि (Law) Unit 3 Part B — RAS Mains उत्तर लेखन कोण

- ◆ 5-अंक के लिए: सीधे Act की परिभाषा से शुरू → 2-3 प्रावधान numbered list में → 1 Rajasthan/real-life example → 1 line निष्कर्ष। लक्ष्य: 70-80 शब्द।
- ◆ 10-अंक के लिए: Act का purpose/background (why it was made) → धाराएं numbered format → 1 landmark case या NCRB data → RAS Officer की भूमिका → निष्कर्ष। लक्ष्य: 130-150 शब्द।
- ◆ RAS Officer की भूमिका हमेशा mention करें: RTI में PIO, PWDVA में Magistrate/Protection Officer, Tenancy में SDM, Revenue में Collector।
- ◆ BNS/BNSS 2023 में IPC/CrPC से बदलाव का angle हमेशा relevant है — यह topic 2026 exam में अवश्य आएगा।

★ परीक्षा में अवश्य पूछे जाने वाले तथ्य ★

1. RTI Act 2005 — धारा 7: सूचना देने की समय-सीमा 30 दिन; जीवन-मृत्यु में 48 घंटे
2. RTI Act — धारा 8(1): 10 exempt categories — राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत जानकारी, संसदीय विशेषाधिकार आदि
3. RTI Act — धारा 20: दंड 250 रु./दिन, अधिकतम 25,000 रु.
4. IT Act 2000 — धारा 66A: Supreme Court ने 2015 में असंवैधानिक घोषित (Shreya Singhal v. Union of India)
5. IT Act 2000 — धारा 66C: Identity Theft — 3 वर्ष + 1 लाख रु. जुर्माना
6. PWDVA 2005 — घरेलू हिंसा: शारीरिक + मानसिक + आर्थिक + यौन हिंसा — सभी शामिल (धारा 3)
7. POCSO 2012 — धारा 19: जानकारी होने पर रिपोर्ट न करना भी दंडनीय (Mandatory Reporting)
8. POSH 2013 — 10 से अधिक कर्मचारियों पर ICC (Internal Complaints Committee) अनिवार्य
9. Senior Citizens Act 2007 — Tribunal: SDM की अध्यक्षता; 90 दिन में निर्णय; अधिकतम 10,000 रु./माह Maintenance

10. IPR — TRIPS Agreement: 1995 से WTO के तहत भारत पर बाध्यकारी; Copyright — 60 वर्ष बाद Public Domain
11. Rajasthan Tenancy Act 1955 — धारा 5 में 31 परिभाषाएं; खातेदार (Khatedar) सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी
12. Rajasthan Land Revenue Act 1956 — Revenue hierarchy: पटवारी → तहसीलदार → SDM → Collector → Board of Revenue
13. BNS 2023 — 1 जुलाई 2024 से लागू; IPC 1860 (511 धाराएं) की जगह 358 धाराएं
14. BNSS 2023 — CrPC 1973 की जगह 531 धाराएं; Trial deadline: 45 दिन
15. BNS 2023 — Zero FIR: किसी भी थाने में FIR दर्ज हो सकती है — jurisdiction की बाधा नहीं
16. IPR — Patent की अवधि: 20 वर्ष; Trademark: 10 वर्ष (नवीकरणीय)
17. PWDVA 2005 — Protection Officer: महिला अधिकारी को प्राथमिकता (धारा 8)
18. RAS Paper 3 Unit 3 Part B — 9 अध्याय: 6 Central Acts + 2 Rajasthan State Acts + 2 Criminal Codes (BNS+BNSS)

महत्वपूर्ण तिथियां एवं ऐतिहासिक क्रम [Important Dates and Historical Timeline]

वर्ष	घटना / अधिनियम / संशोधन
1955	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (Rajasthan Tenancy Act) लागू — काश्तकारों के अधिकार सुनिश्चित
1956	राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम (Rajasthan Land Revenue Act) लागू — राजस्व प्रशासन का आधार
1997	विशाखा दिशा-निर्देश (Vishakha Guidelines) — Supreme Court ने कार्यस्थल यौन उत्पीड़न पर guidelines दिए
2000	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) पारित — भारत में साइबर कानून का आरंभ
2005	सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) पारित — 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी
2005	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (PWDVA) पारित — 26 अक्टूबर 2006 से प्रभावी
2007	माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम (Senior Citizens Act) लागू
2008	IT Act में संशोधन (Amendment) — Sec 66A-F, 67A-C, Cyber Appellate Tribunal जोड़े गए
2012	POCSO Act — बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध विशेष कानून
2013	POSH Act — कार्यस्थल यौन उत्पीड़न कानून (Vishakha Guidelines को कानूनी रूप)
2015	Shreya Singhal v. Union of India — Supreme Court ने IT Act Sec 66A को असंवैधानिक घोषित किया
2023	BNS 2023, BNSS 2023, BSA 2023 (नई आपराधिक संहिताएं) पारित